Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 3, March - 2026

DOIs:10.2018/SS/202603002 --:-- Research Paper / Article / Review

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाँच वर्ष: भारतीय शिक्षा में संरचनात्मक परिवर्तनों की एक समीक्षा

[1] आराधना सिंह, [2] पीपस कुमार

[1]शोधार्थी, मनराखन महतो बी.एड. कॉलेज, रांची, झारखंड, भारत

[2,] सहायक प्राध्यापक, संत जेवियर्स कॉलेज, रांची, झारखंड, भारत

Email - [1] pipasx2gmail.com, [2]aradhana.eco@gmail.com

शोध सार: यह समीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पाँच वर्ष के कार्यान्वयन का आकलन करती है, विशेष रूप से उन मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण है जिन्होंने देश के शैक्षिक परिदृश्य को व्यापक रूप से बदल दिया है। इस अध्ययन में गुणात्मक साहित्य समीक्षा पद्धति का उपयोग करते हुए 2020 से 2025 तक की सरकारी दस्तावेज़ों, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की रिपोर्टों, परिपत्रों, समीक्षित अकादमिक प्रकाशनों, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को, ओईसीडी, विश्व बैंक द्वारा विश्लेषण किया गया शोध कार्य को लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 मे मूलभूत बदलाव किए गए है। पारंपरिक 10+2 संरचना को बदलते हुए संज्ञानात्मक विकास-अनुकूलित 5+3+3+4 पाठ्यचर्या को शामिल किया गया है। इसके साथ चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम; क्रेडिट संचय के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स; ग्रेड 6 से प्रारंभिक व्यावसायिक शिक्षा ; बहु-विषयक और कौशल-वृद्धि पाठ्यक्रम; पूर्व शिक्षण की मान्यता; भारतीय ज्ञान प्रणालियों का समावेशन; मातृभाषा-आधारित बहुभाषी शिक्षा; स्वास्थ्य, योग और पर्यावरण चेतना का समावेश; स्नातक मे अनुसंधान, SWAYAM और DIKSHA प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल विस्तार आदि इसकी प्रमुख विशेषता है। हालाँकि, (एनईपी) 2020 कार्यान्वयन मे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें बुनियादी ढाँचे की अपर्याप्तता, शिक्षकों की कमी, वित्तीय बाधाएँ, आदि शामिल हैं। यह समीक्षा शैक्षिक सुधार को आगे बढ़ाने वाले नीति निर्माताओं के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और शोधकर्ताओं को विकसित भारत 2047 के अनुरूप योग्यता-आधारित, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा की ओर भारत के प्रतिमान बदलाव का एक व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। सफलता के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करके, मजबूत निगरानी ढाँचों और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि भारत के विविध सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में न्यायसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

मुख्य शब्द: एनईपी 2020, भारत में शिक्षा सुधार, व्यवस्थित समीक्षा, संरचनात्मक परिवर्तन, नीति कार्यान्वयन ।

1. प्रस्तावना:

भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी (जनसांख्यिकीय लाभांश) मौजूद है। इस युवा आबादी की क्षमता को सकारात्मक रूप से तभी साकार किया जा सकता है, जब वे व्यावसायिक रूप से सक्षम और वास्तविक अर्थों में शिक्षित हों। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक युगांतकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। यह नीति भारत को शिक्षा के वैश्विक पटल पर एक अग्रणी स्थान दिलाने का लक्ष्य रखती है। कौशल-आधारित शिक्षा पर ज़ोर देते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था और यह जुलाई 2025 में अपने पाँच वर्ष पूरे कर चुकी है। विशेष रूप से, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, इसका प्रावधान बहु आयामी सुधारों और विकास पर केंद्रित है, जिससे शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा सके, विद्यार्थियों के लिए नए द्वार खुलें, और अंततः बेहतर रोज़गार के मार्ग प्रशस्त हों।[1] एनईपी 2020 सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बहुत मौलिक है, जो शिक्षा में पाँच मूलभूत स्तंभों पर केंद्रित है, दूरगामी पहुँच, समानता, सामर्थ्य, जवाबदेही, और गुणवत्ता सुनिश्चित

करना। यह कौशल विकास, अनुभव-आधारित शिक्षा, डिजिटल बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच की परिकल्पना करती है। यह एक व्यापक, अनुकूलनीय, अंतःविषयक शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करती है जो समकालीन वैश्विक मानकों का ध्यान रखती है। यह नीति भारत के अत्यधिक समृद्ध सांस्कृतिक सिद्धांतों को शैक्षिक प्रथाओं में पिरोने का प्रयास करती है, जिससे छात्रों का ऐसा विकास हो जो न केवल कुशल बल्कि नैतिक व्यक्ति भी बने।[2] यह उच्च शिक्षा परिवर्तन के लिए प्राथमिक लक्ष्यों का एक विस्तृत ढाँचा प्रस्तुत करती है, जो 2035 तक के बेंचमार्क स्थापित करती है। आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत पर ज़ोर देते हुए, एनईपी 2020 में अनुकरणीय व्यावसायिक शिक्षा, 2047 तक विकसित और कुशल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।

2. अध्ययन का उद्देश्य

यह शोध पत्र व्यवस्थित समीक्षा पद्धति के माध्यम से एनईपी 2020 का विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसका ध्यान भारतीय शिक्षा के पैटर्न और प्रणाली पर पड़ने वाले तर्कसंगत प्रभाव पर केंद्रित है। सबसे पहले, यह पत्र उन महत्वपूर्ण विशेषताओं और प्रमुख पहलुओं की पड़ताल करती है जो इस नीति को आशाजनक और दूरगामी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न हितधारकों–शिक्षार्थियों, शिक्षकों, और शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया गया है। यह भारतीय शिक्षा में पहुँच, समानता, और प्रणालीगत चुनौतियों को भी संबोधित करता है।[3] सरकारी दस्तावेज़ों, समीक्षित साहित्य, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के विश्लेषण के माध्यम से, यह समीक्षा समानता, गुणवत्ता, और एनईपी सुधारों की निरंतरता से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देती है। कुल मिलाकर, यह समीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा के संरचनात्मक परिवर्तनों का आकलन करती है, जो वैश्विक शैक्षिक पैटर्न के साथ संरेखित हैं।

3. कार्यप्रणाली

हमने गुणात्मक पहलुओं का उपयोग करते हुए व्यवस्थित विश्लेषण के द्वारा एनईपी 2020 की मौलिक गहराई की समीक्षा करने के लिए एक उपागम अपनाया है। हमने मुख्य रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित विभिन्न लेखों, जैसे श्वेत पत्र, नीति दस्तावेज़ों आदि को एकत्र किया और उनकी जाँच की। एनईपी 2020 से संबंधित प्रमुख आधिकारिक दस्तावेज़ों, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्टों, और अन्य शैक्षिक नीति बनाने वाले सरकारी एजेंसियों, जैसे एआईसीटीई (AICTE), आईसीएसएसआर (ICSSR), आईसीएचआर (ICHR), डीएसटी (DST) की रिपोर्टों पर विशेष ध्यान दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की वेबसाइट पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसने इसके लागू होने के बाद से एनईपी 2020 पर सभी नीति कार्यान्वयन दस्तावेज़ प्रकाशित किए हैं।[4] कुछ अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ों, अकादमिक पत्रिकाएँ, जैसे के एडीबी (ADB), ओईसीडी (OECD), यूनेस्को (UNESCO), और विश्व बैंक जैसे प्रतिष्ठित संगठन के रिपोर्टों को भी शामिल किया गया है।

3.1 समावेशन और अपवर्जन मापदंड

इस शोध को प्रभावशाली बनाने के लिए, हमने "नई शिक्षा नीति 2020," "भारतीय शिक्षा सुधार," "एनईपी 2020 कार्यान्वयन," और "शिक्षा नीति विश्लेषण" जैसे मुख्य शब्दों के चयन को प्राथमिकता दी है। इस पद्धति ने विषय पर एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए, वैचारिक अनुसंधान और व्यावहारिक अध्ययन दोनों के समावेश को सक्षम बनाया है।[5] यह समीक्षा समकालीन प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन परिणामों, हितधारक प्रभावों, और डिजिटल शिक्षण की प्रभावशीलता को प्राथमिकता देती है।[6] इस प्रकार, हमारी अनुसंधान पद्धति सैद्धांतिक अध्ययनों पर आधारित है जिनमें वैचारिक ढाँचे शामिल हैं और जो अधिक वास्तविक, विश्वसनीय और निष्कर्ष प्रस्तुत करने वाली वर्तमान परिस्थिति को दर्शाते हैं।

4. एनईपी 2020 की मुख्य बातें

4.1 स्कूल पाठ्यचर्या में संरचनात्मक परिवर्तन

एनईपी 2020 एक दूरदर्शी नीति है जो भारत के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है।[7] एनईपी 2020 का एक मुख्य लक्ष्य बुनियादी साक्षरता पर ज़ोर देना और कौशल-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहु-विषयक शिक्षा को शामिल करना है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बदलाव में पारंपरिक 10+2 मॉडल का नए 5+3+3+4 ढाँचे से प्रतिस्थापन है, जो शैक्षिक चरणों को संज्ञानात्मक विकास को संरेखित करता है। यह बुनियादी (उम्र 3-8), प्रारंभिक (8-11), मध्य (11-14), और माध्यमिक (14-18) संरचना को प्रस्तावित करता है।[4] यह संरचना खेल-आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक तरीकों और विषय विकल्पों को बढ़ावा देती है। योग्यता-आधारित शिक्षा ने रटने को प्रतिस्थापित कर दिया है, जो आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है, जिसमें कोडिंग, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए गए हैं।[8]

4.2 शिक्षकों की क्षमता निर्माण में वृद्धि

निष्ठा और MMTTP जैसी प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से शिक्षक क्षमता को बढ़ाने की प्राथमिकता दी गई है। एनसीईआरटी (NCERT) और एससीईआरटी (SCERTs) ने एनईपी 2020 के दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए पाठ्यक्रम ढाँचों को संशोधित किया है।[6] सामूहिक रूप से, इन सुधारों का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक लोकाचार में निहित एक समावेशी, शिक्षार्थी-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली बनाना है।

4.3 कॉलेज शिक्षा में परिवर्तनकारी बदलाव

एनईपी एकल-संकाय संस्थानों से बहु-संकाय संस्थानों को बढ़ावा देता है। कॉलेज शिक्षा के लिए सबसे पहला संरचनात्मक परिवर्तन तीन-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का विस्तार करके चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम किया गया है, जिसका उद्देश्य इसे अधिक लचीला, समावेशी और विश्व स्तर का बनाना है।[9] हालाँकि, तीन साल पूरे करने के बाद भी निकास का विकल्प अभी भी अपनी जगह पर बरकरार है। अतिरिक्त वर्ष का उद्देश्य छात्रों को अनुसंधान तंत्र और विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने वाले रोजगार के लिए तैयार करना है। एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदुओं की शुरुआत, छात्रों को उनकी अध्ययन अवधि के आधार पर प्रमाण पत्र यानि, डिप्लोमा या डिग्री मिलने का प्रवधान है।[8] यह प्रवधान अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स द्वारा किया जाएगा है, जो एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो संस्थानों के बीच क्रेडिट संचय और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, जिसमें ऑनलाइन डिग्रियाँ प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है और नामांकन में चार गुना वृद्धि हुई है।[5] व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में एकीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने 1.5 लाख से अधिक इंटर्नशिप ऑफ़र की सुविधा प्रदान की है। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक और मील का पत्थर है, जिसमें अब शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन ने गुरुग्राम में अपना परिसर खोला, और 2027 तक पाँच और परिसरों के खुलने की उम्मीद है।

4.4 पूर्व कौशल को मान्यता देना

एनईपी 2020 समावेशी और लचीली शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए पूर्व शिक्षण और कौशल की पहचान पर ज़ोर देती है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पारंपरिक शैक्षणिक रास्तों के बाहर–कार्य अनुभव, व्यावसायिक प्रशिक्षण, या अनौपचारिक शिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के

लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।[10] यह उपागम आजीवन सीखने का समर्थन करता है और प्रदर्शित दक्षताओं के लिए छात्रों को शैक्षणिक क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देकर रोजगार क्षमता को बढ़ाता है। यूजीसी विश्वविद्यालयों को कौशल-आधारित मॉड्यूल को एकीकृत करने और पूर्व शिक्षण को मान्य व प्रमाणित करने के लिए उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

4.5 बहु-विषयक शिक्षा के रूप में सामान्य विषयों का समावेश

एनईपी 2020 में विषय और पाठ्यक्रम बहुत व्यापक है। इस उपागम ने छात्रों को अपनी पसंद और कौशल के विषय का अध्ययन करने का प्रवधान है, जिससे उन्हें नवाचार उत्प्रेरक और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देते हुए अपने कौशल को बढ़ाने का मौका मिला है। स्कूल पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है जो बच्चों को विभिन्न विषय में विभिन्न धाराओं का चयन करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र संगीत के साथ रसायन विज्ञान या फैशन डिजाइन या कोडिंग जैसे व्यावसायिक विषयों के साथ इतिहास का अध्ययन कर सकता है।

4.6 व्यावसायिक शिक्षा

एनईपी 2020 ग्रेड 6 से व्यावसायिक मॉड्यूल को एकीकृत करके और उन्हें उच्च शिक्षा में विस्तारित करके शिक्षा और रोजगार के बीच के अंतर को कम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि छात्र बाज़ार-प्रासंगिक योग्यताएँ प्राप्त करें। रटने की प्रथा जो भारतीय शिक्षा प्रणाली पर हावी रही, उसे प्रायोगिक शिक्षण के मापदंडों के माध्यम से संबोधित किया गया जिसने एक छात्र केंद्रित प्रणाली प्रदान को प्रोत्साहित करती है, जहाँ छात्र स्वयं को मेंटर-मेंटी, इंटर्नशिप के अवसर, और आउटरीच गतिविधियों के रूप में विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो सके।[11]

4.7 कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम

एनईपी 2020 मुख्यधारा की शिक्षा में कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम को शामिल करके छात्र-केंद्रित उपागम को बढ़ावा देती है। ये पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को उनकी रुचियों और करियर लक्ष्यों के साथ संरेखित विषयों को चुनने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे व्यक्तिगत शिक्षण मार्ग को बढ़ावा मिलता है।[9] व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, और परियोजना-आधारित शिक्षण पर ज़ोर देकर, छात्र व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं और आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, और समस्या-समाधान कौशल विकसित करते हैं। इसके अतिरिक्त, कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम पूर्व शिक्षण और अनौपचारिक प्रशिक्षण को मान्यता देकर छात्रों को लाभ पहुँचाते हैं, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण होता है।[12] कुल मिलाकर, एनईपी 2020 का कौशल विकास पर ज़ोर, परीक्षा-केंद्रित प्रणालियों से शिक्षार्थी-संचालित मॉडल की ओर बदलाव को दर्शाता है जो अनुभव, अनुकूलनशीलता और समग्र विकास को महत्व देता है–यह छात्रों को केवल नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक समाज में सार्थक भागीदारी के लिए तैयार करता है।

4.8 भाषा विज्ञान पर ध्यान

एनईपी 2020 में भाषा विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो विविध संदर्भों में भाषा को सिखाने, सीखने और महत्व देने के तरीके को बदल सकता है। विज्ञान–भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन–ध्वनि विज्ञान व्याकरण, अर्थ विज्ञान, और समाज-भाषा विज्ञान को समझने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जो बहुभाषी दक्षता और समावेशी शिक्षाशास्त्र के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। एनईपी 2020 प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को निर्देश का माध्यम बनाने पर ज़ोर देती है, जो भाषाई अनुसंधान द्वारा समर्थित है जो दर्शाता है कि बच्चे अपनी पहली भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं।[13] यह बदलाव न केवल बुनियादी साक्षरता में सुधार करता है, बल्कि संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करता है। शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम डिज़ाइन में भाषा विज्ञान को एकीकृत करके, शिक्षक उच्चारण, वाक्यविन्यास, और भाषा अधिग्रहण की चुनौतियों को

बेहतर ढंग से संबोधित कर सकते हैं।[14] इसके अलावा, यह नीति द्विभाषी और त्रिभाषी दक्षता को बढ़ावा देती है, छात्रों को कम से कम तीन भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालिया अनुभवजन्य आकलन त्रि-भाषा सूत्र को लागू करने में मिश्रित परिणाम दर्शाते हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों में हितधारकों की स्वीकृति और शिक्षाशास्त्रीय प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं।

4.9 स्वास्थ्य और योग

एनईपी 2020 स्वास्थ्य और योग को मुख्य पाठ्यक्रम तत्वों के रूप में एकीकृत करके भारतीय शिक्षा में क्रांति लाती है, जो पारंपरिक शैक्षणिक-केंद्रित शिक्षा से समग्र विकास की ओर एक प्रतिमान बदलाव को चिह्नित करती है।[15] यह एकीकरण एक साथ मानसिक कल्याण, शारीरिक स्वास्थ्य, और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण समय पर आया है जब बच्चों का स्वास्थ्य, खुशी और प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य और योग का एकीकरण प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर उच्च शिक्षा तक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और माइंडफुलनेस को मुख्य पाठ्यक्रम में समाहित करता है। योग, एक समय-परीक्षणित भारतीय अभ्यास, को केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं, बल्कि भावनात्मक विनियमन, एकाग्रता और आंतरिक संतुलन के लिए एक उपकरण के रूप में पेश किया जाता है।

4.10 भारतीय ज्ञान प्रणाली पर ध्यान

एनईपी 2020 भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर अभूतपूर्व ज़ोर देती है, जो सांस्कृतिक रूप से निहित और समग्र शिक्षण की ओर एक प्रतिमान बदलाव को चिह्नित करता है।[15] इस पहल में भारत के बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए अपार दीर्घकालिक क्षमता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली जिसमें प्राचीन विज्ञान, कला, दर्शन, स्वास्थ्य प्रणालियाँ, और पारिस्थितिक ज्ञान शामिल हैं–को पाठ्यक्रमों में समाहित करके, एनईपी 2020 शिक्षार्थियों के बीच पहचान, गौरव और निरंतरता की भावना को बढ़ावा देती है।[8] यह आयुर्वेद, योग, वास्तु, धातुकर्म और गणित जैसे पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित करती है, जो स्वदेशी ढाँचों में निहित अंतर-विषयक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। यह न केवल शैक्षणिक विमर्श को समृद्ध करता है बल्कि भारत को नैतिक ज्ञान प्रणालियों के लिए एक वैश्विक योगदानकर्ता के रूप में भी स्थापित करता है।

4.11 स्नातकों के लिए अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र

एनईपी 2020 स्नातक छात्रों के लिए एक अनुसंधान तंत्र की परिकल्पना करती है, जो निष्क्रिय शिक्षण से सक्रिय जाँच की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है।[9] उच्च शिक्षा में अनुसंधान के अवसरों को समाहित करके, एनईपी 2020, छात्रों को केवल ज्ञान का उपभोक्ता होने के बजाय निर्माता बनने के लिए सशक्त बनाती है। छात्रों के लिए, यह उपागम आलोचनात्मक सोच, जिज्ञासा और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। अनुसंधान पद्धतियों, अंतर-विषयक परियोजनाओं और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के संपर्क में आने से उनका शैक्षणिक जुड़ाव बढ़ता है और वे उन्नत अध्ययन या नवाचार-संचालित करियर के लिए तैयार होते हैं। संस्थागत रूप से, यह नीति बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (MERUs) के विकास को प्रोत्साहित करती है और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) जैसी पहलों का समर्थन करती है, जो विषयों में छात्र-नेतृत्व वाले अनुसंधान को वित्त पोषित करती है।

4.12 पर्यावरणीय देखभाल को बढ़ावा देना

एनईपी 2020 शैक्षिक चेतना को शिक्षा में समाहित करके प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर उच्च शिक्षा तक, छात्रों के बीच पर्यावरण संबंधी देखभाल को बढ़ावा देती है। यह मानती है कि स्थिरता केवल एक विषय नहीं है बल्कि जीवन का एक तरीका है, और इसका लक्ष्य पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और संस्थागत प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण के प्रति

जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। स्कूल स्तर पर, पर्यावरण शिक्षा को विषयों और चरणों में एकीकृत किया जाता है। नई 5+3+3+4 संरचना मूलभूत वर्षों में प्रकृति-आधारित शिक्षा का परिचय देती है, जो बच्चों को खेल और अवलोकन के माध्यम से अपने परिवेश का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है।[4] जैसे-जैसे छात्र प्रगति करते हैं, वे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, जल संरक्षण, जैसे विषयों से अनुभवात्मक गतिविधियों, परियोजनाओं और स्थानीय केस स्टडी के माध्यम से जुड़ते हैं।

5. कार्यान्वयन रणनीति और प्रभाव विश्लेषण

यह खंड एनईपी 2020 के 5 वर्षों के शैक्षिक परिणामों की एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है। भारत में शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकारों को अपनी क्षेत्रीय सीमा के भीतर शिक्षा के लिए कानून बनाने की पूरी स्वायत्तता है। समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने एनईपी 2020 को लागू नहीं किया है। हालाँकि अधिकांश राज्यों द्वारा अपनाया गया, एनईपी 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, यद्यपि अनुभवजन्य प्रमाण अंगीकरण के तरीकों, कार्यान्वयन समय-सीमाओं और संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय भिन्नताओं को उजागर करते हैं।[9] बढ़ी हुई छात्र संख्या को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढाँचे की कमी प्राथमिक बाधा है।

नीति के लिए शैक्षिक बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है, जिसे प्रदान करने के लिए कई राज्य संघर्ष कर रहे हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, प्रशासनिक बाधाएँ, और बदलाव का प्रतिरोध अन्य चुनौतियों में शामिल हैं। नीति को लागू करने के लिए अच्छी तरह से योग्य निर्देशात्मक पेशेवरों के प्रेरण के साथ-साथ वर्तमान शिक्षण कर्मचारियों के व्यापक क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग जैसी प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा ने एनईपी 2020 में डिजिटल विभाजन को बढ़ाया है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित शिक्षण संस्थानों के लिए।

सामाजिक-आर्थिक विविधता, भाषा बाधा और सांस्कृतिक परिदृश्य एनईपी 2020 के समान कार्यान्वयन को कठिन बनाते हैं। इस नीति ने विभिन्न विद्वानों और शिक्षा विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण आलोचना की है जो तर्क देते हैं कि इसका तेज़ी से कार्यान्वयन न्यायसंगत शिक्षा को कमजोर कर सकता है। छात्रों के दृष्टिकोण से, अत्यधिक बोझिल पाठ्यक्रम और प्रति सेमेस्टर पेपर की संख्या में वृद्धि ने विभिन्न छात्र निकायों से आलोचना की है। छात्र जागरूकता और धारणा की जाँच करने वाले अनुभवजन्य अध्ययन, लचीलेपन और अंतर-विषयकता के लिए सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ पाठ्यक्रम अधिभार, मूल्यांकन बोझ, और अपर्याप्त संस्थागत समर्थन प्रणालियों के बारे में चिंताओं को प्रकट करते हैं।[3]

एनईपी 2020 ने भारत के सकल नामांकन अनुपात (GER) को संबोधित करने की कोशिश की है। एनईपी 2020 ने 2030 तक पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को अनिवार्य किया है, लेकिन यह काफी चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतीत होता है। हालाँकि, यदि ऐसा किया जाता है तो एक अधिक कुशल और अनुकूलनीय कार्यबल विकसित होने की संभावना है, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर अनुकूल है। एनईपी 2020 में व्यावसायिक प्रशिक्षण और बहु-विषयक शिक्षा उल्लेखनीय हैं, लेकिन यह विषय-विशिष्ट विशेषज्ञता के तनुकरण का कारण बन सकता है। एक प्राथमिक कठिनाई, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में, व्यापक शिक्षा और विशेष विशेषज्ञता के लक्ष्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

6. एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

यद्यपि एनईपी 2020 एक महत्वपूर्ण शैक्षिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करती है, इसके कार्यान्वयन को पर्याप्त बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नीति का निष्पादन अपर्याप्त भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचे, योग्य शिक्षकों की कमी, डिजिटल असमानता, और सीमित वित्तीय संसाधनों से बाधित है।

शैक्षणिक संस्थानों को व्यापक संकाय विकास कार्यक्रमों, नवीन शिक्षण पद्धतियों को समायोजित करने के लिए व्यापक पुनः कौशल पहलों, और सुधारे गए मूल्यांकन ढाँचों के अनुकूलन की आवश्यकता है। नए शैक्षिक उपागमों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता के साथ-साथ शिक्षण कार्यबल का विस्तार करने की आवश्यकता को देखते हुए जटिलता बढ़ जाती है।

क्षेत्रीय असमानताएँ एक और बाधा प्रस्तुत करती हैं, जिसमें विभिन्न सामाजिक-आर्थिक खंडों में शैक्षिक पहुँच और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ हैं। ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँचने में असमान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे एक असमान कार्यान्वयन परिदृश्य बनता है। हाल के अनुभवजन्य प्रमाण दर्शाते हैं कि शासन संरचनाएँ, संसाधन वितरण तंत्र, और जवाबदेही ढाँचे गहरी जड़ें जमा चुकी समानता की चिंताओं को दूर करने के लिए अपर्याप्त बने हुए हैं।

डिजिटल बुनियादी ढाँचे का अंतर विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जहाँ अपर्याप्त कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच नीति के डिजिटल शिक्षण उद्देश्यों में बाधा डालती है। डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों के अनुभवजन्य आकलन शहरी और ग्रामीण संदर्भों के बीच पहुँच, उपयोग पैटर्न और सीखने के परिणामों में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ प्रकट करते हैं, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी एकीकरण को पर्याप्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।[16]

वित्तीय बाधाएँ इन चुनौतियों को बढ़ा देती हैं, क्योंकि व्यापक सुधारों को लागू करने के लिए बुनियादी ढाँचे, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और तकनीकी एकीकरण में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत सार्वजनिक-निजी सहयोग, शिक्षकों के लिए केंद्रित क्षमता-निर्माण पहल, और प्रभावी कार्यान्वयन और जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधार सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निगरानी ढाँचे शामिल हैं।

7. निष्कर्ष: शिक्षा के लिए आगे का रास्ता

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनईपी 2020 के सुधारों से समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ हो, इन विसंगतियों को दूर करना महत्वपूर्ण है। समय के साथ, पाठ्यक्रम ढाँचा साल-दर-साल एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है। परिणाम-आधारित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण बाधाएँ आई हैं।

कई शैक्षणिक संस्थान, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में, भौतिक बुनियादी ढाँचे और डिजिटल कनेक्टिविटी दोनों एक महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। योग्य शिक्षकों की कमी एक चिंता बनी हुई है, न केवल संख्या के संदर्भ में, बल्कि शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण विधियों के लिए कौशल उन्नयन, और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणालियों के अनुकूलन की आवश्यकता के संदर्भ में भी।

डिजिटल विभाजन बना हुआ है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। वित्तीय बाधाएँ संस्थानों के विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रयासों को और जटिल बनाती हैं, जिससे सुधारों की पहुँच और प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। शैक्षिक गुणवत्ता और पहुँच में क्षेत्रीय असंतुलन

न्यायसंगत कार्यान्वयन को चुनौती देना जारी रखते हैं। भाषा बाधाएँ, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, और राज्यों में नीतिगत उपायों को अपनाने में असमानता समान प्रगति में बाधा डालती हैं। इसके अतिरिक्त, मजबूत निगरानी ढाँचों की कमी और केंद्र, राज्य और संस्थागत हितधारकों के बीच समन्वय की कमी सुधार की गति को धीमा कर देती है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, सार्वजनिक-निजी सहयोग को मजबूत करना, शिक्षकों के लिए लक्षित क्षमता विकास में निवेश करना, और मूल्यांकन और जवाबदेही के लिए मजबूत प्रणालियों की स्थापना करना आवश्यक है। भारत भर के सभी शिक्षार्थियों के लिए एनईपी 2020 के समावेशी, उच्च-गुणवत्ता वाले और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ

1. अंकोर एस. भारत की शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। आइडियलिस्टिक जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च। 2025;4(4):26–31.

2. गुप्ता ए, पाल एस. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक उत्तरदायित्व: एक विश्लेषण। शोधकोष: दृश्य एवं कला प्रदर्शन पत्रिका। 2023;4(2):4722–4730.

3. जैन ए. एनईपी 2020 और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: चुनौतियाँ एवं अवसर। ज्ञानोदय रिसर्च जर्नल। 2021;17(3):110–125.

4. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय; 2020। उपलब्ध: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

5. चौकसे एलएल. उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषणात्मक अध्ययन। इन्स्पिरा जर्नल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2024;14(1):5–18.

6. द्विवेदी पी. नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS): शिक्षाशास्त्र एवं दर्शन। भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका। 2022;8(3):112–125.

7. चौहान वी. एनईपी 2020 के संदर्भ में शिक्षक क्षमता निर्माण और NISHTHA पहल की प्रभावशीलता। अधिगम शोध पत्रिका। 2022;9(4):180–195.

8. यादव एस. एनईपी 2020 द्वारा उच्च शिक्षा में किए गए परिवर्तन: चुनौतियाँ और समाधान। सामाजिक विमर्श। 2023;18(4):50–65.

9. त्रिपाठी के. उच्च शिक्षा में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण: एनईपी 2020 की प्राथमिकता। रिसर्च एंड इनोवेशन इंडिया। 2022;19(4):60–72.

10. राव एल. क्रेडिट संचय और एबीसी (ABC): छात्रों के लिए लचीलेपन की नई राह। उच्च शिक्षा मंथन। 2024;13(2):160–175.

11. रेड्डी जी. एनईपी 2020 के तहत स्कूल पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 संरचना का प्रभाव। समग्र शिक्षा विमर्श। 2023;11(1):40–55.

12. वर्मा ए. चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP): अवधारणा एवं क्रियान्वयन की कठिनाइयाँ। शिक्षा और समाज। 2022;7(1):10–24.

13. शर्मा एम. एनईपी 2020: समता, गुणवत्ता और पहुँच के आधार स्तंभ। शैक्षणिक विमर्श। 2021;12(1):22–35.

14. शर्मा आर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) का महत्व। नवीन शोध पत्रिका। 2023;9(6):156–168.

15. सिंह आरके. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा का समावेश। समाज विज्ञान शोध पत्रिका। 2021;15(2):45–58.

16. व्यास आर. व्यावसायिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से एकीकरण: एनईपी 2020 की पहल। कौशल विकास पत्रिका। 2024;3(1):15–28.

17. गुर्जर एम. एनईपी 2020 और क्षेत्रीय असमानताएँ: समान कार्यान्वयन की चुनौतियाँ। विकास और नीति समीक्षा। 2022;9(1):35–49.

18. झा केएल. बहु-विषयक उपागम और क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली: भारतीय संस्थानों में अनुकूलन। प्रगतिशील शिक्षा। 2024;10(2):78–90.

19. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएँ: उच्च शिक्षा। नई दिल्ली: UGC; 2020। उपलब्ध: https://www.ugc.gov.in/pdfnews/0144334_hindi_he-final-31072020.pdf

20. Asian Development Bank (ADB)। Education Sector Directional Guide। Manila: ADB; 2023। उपलब्ध: https://www.adb.org/sites/default/files/page/813361/education-sector-directional-guide.pdf

21. UNESCO। State of Education Report 2025 [Internet]। Paris: UNESCO; 2025। उपलब्ध: https://articles.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2025/12/SOER%202025_Digital.pdf